

उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण हेतु उद्योग बन्धु ने आयोजित की त्रिपक्षीय बैठकें

- प्रतीक्षारत् उद्योगों को चोला तथा अन्य स्थानों पर प्राथमिकता के आधार पर भूमि आवंटित की जाएगी
- मुरादाबाद एसईजेड में दो बहु-उत्पाद जोन बनाने का प्रस्ताव

लखनऊ, 22 जुलाई 2013

राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में बेहतर औद्योगिक माहौल बनाने के लिए उठाये गए विभिन्न कदमों के अनुक्रम में आज 'उद्योग बन्धु' के अधिशासी निदेशक व प्रमुख सचिव- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, डॉ. सूर्य प्रताप सिंह की अध्यक्षता में उद्यमियों की लम्बित समस्याओं के केस-टू-केस आधार पर निराकरण हेतु त्रिपक्षीय बैठकों का सिलसिला आरम्भ हुआ।

आज सम्पन्न त्रिपक्षीय बैठक में उद्यमी, औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि, उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम लि. (यूपीएसआइडीसी) एवं अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। इसमें प्रमुख रूप से औद्योगिक प्लांटों के ऊपर से गुजरने वाली विद्युत पारेषण लाइनों के विस्थापन, अग्निशमन केन्द्रों की स्थापना तथा औद्योगिक भूखण्डों के आवंटन से सम्बन्धित प्रकरणों को हल करने के लिए विचार-विमर्श किया गया।

आज कुल 21 मामलों पर विचार किया गया, जिसमें से अधिकतर प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण के लिए दिशा-निर्देश दिए गए।

प्रमुख सचिव- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, डॉ. सूर्य प्रताप सिंह ने उ. प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम को निर्देशित किया कि एक अद्यावधिक डायरेक्ट्री तैयार करे जिसमें खाली व आवंटन निरस्त किए गए औद्योगिक भू-खण्डों का विवरण हो तथा इन भू-खण्डों को लम्बित आवेदकों को आवंटित किया जाए। डॉ. सिंह ने अग्निशमन विभाग को निर्देशित किया कि वे यूपीएसआइडीसी से समन्वय कर औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि की कमी के दृष्टिगत वर्टिकल अग्निशमन केन्द्रों को स्थापित करें।

गाजियाबाद इण्डस्ट्रीज़ फेडरेशन के इस निवेदन पर कि सिकन्दराबाद औद्योगिक क्षेत्र के प्रतीक्षारत् उद्यमियों को भू-खण्ड आवंटन किया जाए, यह निर्णय लिया गया कि यूपीएसआइडीसी इन उद्यमियों को निरस्त किए गए आवंटनों में से तथा बुलन्दशहर में प्रस्तावित चोला औद्योगिक क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर भू आवंटन करे।

यूपीएसआइडीसी के प्रबन्ध निदेशक, मनोज सिंह ने सूचित किया कि यूपीएसआइडीसी ने मुरादाबाद विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (एसईजेड) में दो गतिविधियों वाले दो जोन स्थापित करने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा है, जिसका उत्तर अपेक्षित है।

इण्डियन इण्डस्ट्रीज़ एसोसिएशन द्वारा मथुरा के निकट गैस आधारित प्रदूषणरहित औद्योगिक क्षेत्र का विकास करने की मांग पर निर्णय लिया गया कि यूपीएसआइडीसी सार्वजनिक-निजी सहभागिता (पीपीपी) पर इसके लिए तैयार है, किन्तु भूमि का प्रबन्ध या तो इच्छुक उद्यमी स्वयं करें या यूपीएसआइडीसी को भूमि अधिग्रहण के लिए धनराशि उपलब्ध करायें।

बैठक में यूपीएसआइडीसी के प्रबन्ध निदेशक, मनोज सिंह, उद्योग बन्धु के संयुक्त अधिशासी निदेशक-डा. कौशलराज शर्मा सहित उद्यमियों तथा अग्निशमन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया।

इसी प्रकार की त्रिपक्षीय बैठकों का आयोजन आगामी दो दिनों में भी किया जाएगा। तीन दिन चलने वाली इस प्रक्रिया में उद्यमियों के कुल 47 पूर्व इंगित मामलों को हल किये जाने का प्रयास किया जाएगा।

ज्ञात हो कि उद्योग बन्धु प्रदेश में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार की नोडल संस्था है, जो उद्यमियों के लम्बित मामलों के निवारण के लिए त्रिपक्षीय बैठक आयोजित कराता है, जिसमें उद्यमी व सम्बन्धित विभाग के मध्य बैठक कराई जाती है और निर्णय लिये जाते हैं।